Financial Assistance for Modernisation of Powerloom in Gujarat

2047. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Gujarat Government has sent any proposal for providing financial assistance for the modernisation of powerlooms in that State; and

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No, Sir.

(b) Doesn't arise.

Restructuring the Capital Base of NTC

2048. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to restructure the capital base of the National Textile Corporation;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the reasons for restructuring the capital base of NTC;

(d) how much outlay is envisaged in the restructuring plans and how this outlay is proposed to be raised; and

(e) what is the extent of losses suffered by NTC during each of the last three years and what steps Government have taken in this regard so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (e) The losses suffered by the NTC during the last three years are as follows :—

(Rs. in crores)

1991-92 (Audited)	– 313.93
1992-93 (Audited)	– 684.52*
1993-94 (Provisional)	– 659.63*

*inclusive of the interest on Government loans.

Budgetary support of Rs. 73 crores was provided by the Government to the NTC in 1991-92 to offset the cash losses. Similarly, in 1992-93, Rs. 154.8 crores and in 1993-94 Rs. 132 crores were provided.

The Textile Research Associations (TRAs) have prepared Rehabilitation Scheme for revival of the NTC mills. The TRAs' Schemes envisage, among other things, financial restructuring of the mills. The TRAs have proposed such restructuring in view of the fact that losses have accumulated, the net worth has been eroded, and Banks/Financial Institutions are reluctant to extend further financial support to the NTC mills. Action is underway to formalise the Government stand for acceptance by the BIFR so that the Turn Around Plan can be implemented.

Sick Textile Mills

2049. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of textile mills which have fallen sick in private sector, joint sector and public sector during the last three years;

(b) the reasons for the sickness of those textile mills;

(c) the States where these mills are located; and

(d) the steps taken to revive these textile mills?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Cases of 52 textile mills were registered with Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR) as sick from January 92 to 30-6-94 as per the following details:

Public Sector (NTC, BIC, STC)	: 25
Private Sector	: 27

(b) The reasons for sickness is mainly financial problems.

(c) These mills are located mainly in Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat.

(d) BIFR has been established by the Government to evolve and manage rehabilitation packages in respect of viable sick/closed textile mills.

कपड़ा मिलों को बंद किया जाना

2050. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कपड़ा उद्योग में उत्पन्न अवरोधों के कारण 1175 मिलों में से 132 कपड़ा मिलें पूर्णतया बंद हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन बंद मिलों में मार्च, 1994 तक कुल कितना पूंजी निवेश था और उनमें कार्य कर रहे स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि सूती वस्त्र संबंधी औद्योगिक समिति की हाल में हुई त्रिपक्षीय बैठक में 1985 में घोषित कपड़ा नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता अनुभव की गई ;

(घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पिछली कपड़ा नीति में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) (क) 29 मिलें सरकारी समापन के अधीन हैं। 30-6-1994 को विभिन्न कारणों से 100 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें अस्थाई रूप से बंद पड़ी हैं। लेकिन आई डी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूती मानव/निर्मित फाइबर मिल बद नहीं है।

(ख) मिलों का बंद होना सामान्यतः अस्थाई होता है। कुछ बंद पड़ी हुई मिलें दुबारा खुल जाती हैं जबकि कुछ चालू मिलें अस्थाई रूप से पुनः बंद हो जाती हैं इसलिए उसमें लगे निवेश में परिवर्तन होता रहा है। 31-3-1994 तक की स्थिति के अनुसार इन मिलों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 1.73 लाख थी।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) समिति के सदस्यों को यह बता दिया गया है कि वस्त्र नीति के मौजूदा उपबंधों को उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना गया है। यह भी बताया गया था कि नीति की पुनरीक्षा एक सतत प्रक्रिया है तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जाता है।

कपड़े का उत्पादन

2051. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्री राम जेठ मलानी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़े का उत्पादन मुख्यतः मिलों, हथकरघों तथा विद्यूतकरघों के तीन क्षेत्रों में किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में कपड़े का वर्ष-वार कितना-कितना उत्पादन किया गया ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग वर्ष में इन क्षेत्रों में नियोजित लोगों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर प्रति वर्ष खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन निम्नानुसार रहा है :